ई संदेश

21 मई, 2026 | अंक - 206

सात दिन, सात पृष्ठ

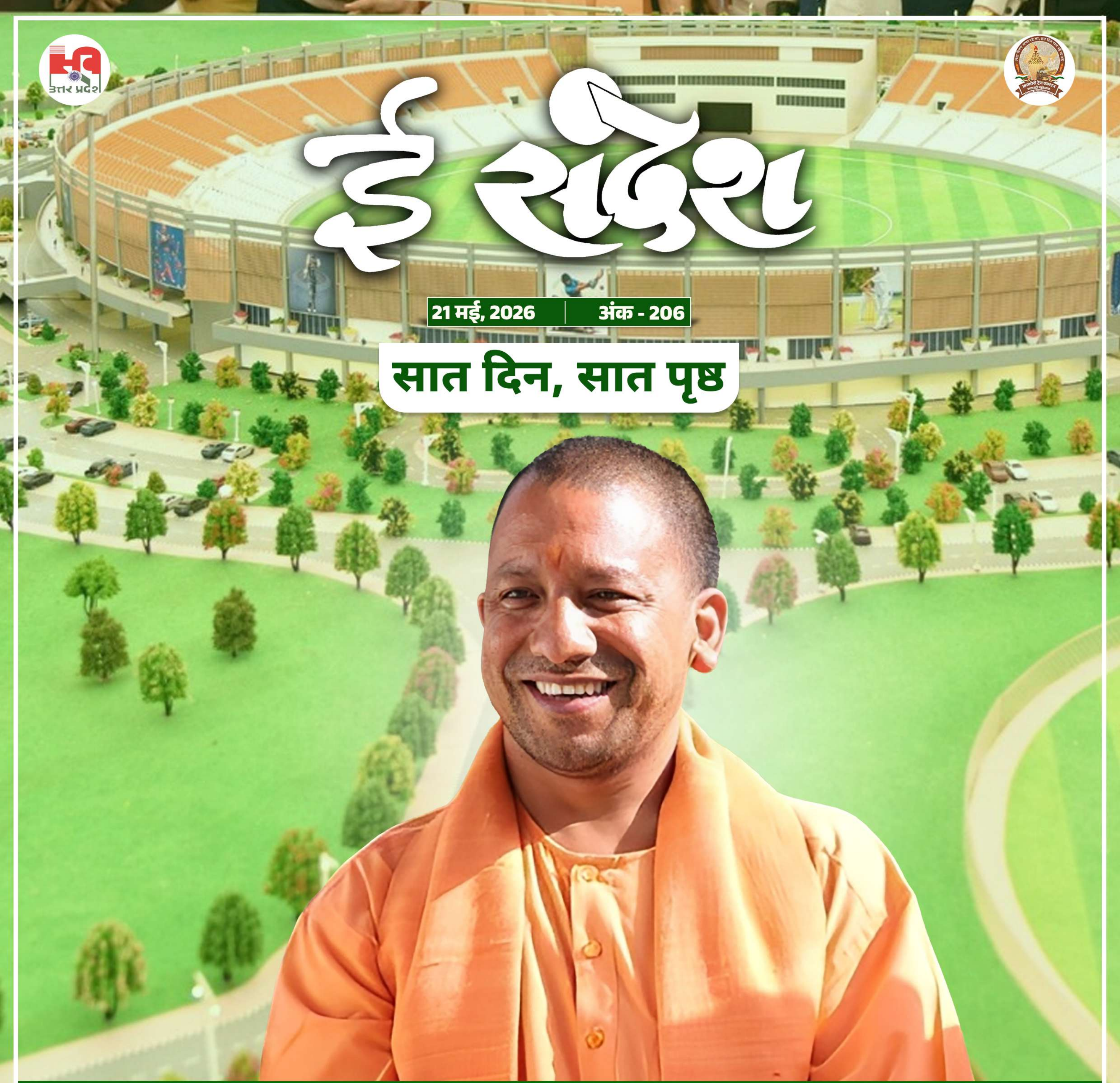

- सुरक्षा सुशासन और मजबूत बुनियादी ढांचे के दम पर देश का सर्वश्रेष्ठ निवेश गंतव्य बनकर उभरा नया उत्तर प्रदेश
- सुदृढ़ बुनियादी ढांचे और लोक कल्याणकारी नीतियों से देश के विकास का मुख्य ग्रोथ इंजन बना नया उत्तर प्रदेश
- उत्तर प्रदेश के खेल इन्फ्रास्ट्रक्चर में हुआ इज़ाफ़ा, गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण कार्यों का हुआ भूमिपूजन
- अनुदेशकों को मिली मानदेय में भारी वृद्धि और कैशलेस स्वास्थ्य सुरक्षा
- पारदर्शी चयन प्रणाली से उत्तर प्रदेश को मिले नौ सौ बत्तीस नए प्रशासनिक कर्णधार
- मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में प्रस्तुत हुआ उत्तर प्रदेश के अभूतपूर्व विकास का मॉडल
- यू0पी0 डाटा सेण्टर क्लस्टर परियोजना उत्तर प्रदेश के ए0आई0 मिशन की बुनियादी संरचना तैयार करेगी
- शिष्टाचार भेंट
- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में 18 मई, 2026 को मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

नए भारत का नया उत्तर प्रदेश

सुरक्षा सुशासन और मजबूत बुनियादी ढांचे के दम पर देश का सर्वश्रेष्ठ निवेश गंतव्य बनकर उभरा नया उत्तर प्रदेश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 14 मई, 2026 को लखनऊ में आयोजित 'डिफाइनिंग 09 ईयर्स ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन' कॉन्क्लेव में उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा पर अपने महत्वपूर्ण विचार साझा किए। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन में राज्य नीति, नियत और दृढ़ संकल्प के साथ प्रगति के पथ पर लगातार आगे बढ़ रहा है। अब प्रदेश का विकास कुछ चुनिंदा शहरों तक सीमित नहीं होकर सभी 75 जनपदों में समान रूप से दिखाई दे रहा है।

उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों के समय राज्य में व्याप्त अराजकता और पिछड़ेपन का जिक्र करते हुए कहा कि एक दशक पहले उत्तर प्रदेश की पहचान एक प्रश्न प्रदेश और बीमारू राज्य के रूप में बन गई थी। उस दौर में युवाओं के सामने पहचान का संकट बना हुआ था, किसान और व्यापारी परेशान थे तथा पर्व-त्योहारों से पहले कानून-व्यवस्था बिगड़ जाती थी।

वर्ष 2017 में राज्य का बजट केवल ढाई लाख करोड़ रुपये के आसपास हुआ करता था, जो विशाल आबादी के लिए बेहद कम था। डबल इंजन सरकार ने कड़े फैसले लेते हुए बिना किसी भेदभाव के नीतियां बनाईं और भाई-भतीजावाद पर पूरी तरह लगाम कसी। पारदर्शी कार्ययोजनाओं के क्रियान्वयन से राज्य की तस्वीर में अभूतपूर्व बदलाव देखने को मिला।

वर्तमान में देश के कुल एक्सप्रेस-वे नेटवर्क का 60 प्रतिशत हिस्सा अकेले उत्तर प्रदेश में मौजूद है, जिससे राज्य के कोने-कोने तक कनेक्टिविटी सुगम हो गई है। जेवर में बन रहा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आगामी 15 जून से अपनी वायु सेवाएं शुरू करने जा रहा है, जिससे यह क्षेत्र देश का एक बड़ा लॉजिस्टिक और एमआरओ हब बनकर उभरेगा।

राज्य के सात प्रमुख शहरों में मेट्रो का सफल संचालन हो रहा है और देश की पहली रैपिड रेल दिल्ली-मेरठ के बीच गति पकड़ चुकी है। कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी सुधार करते हुए एग्रीकल्चरल ग्रोथ को 8 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत तक पहुँचाया गया है। वर्तमान में लगभग 50 लाख हेक्टेयर भूमि को नहरों और ट्यूबवेल के जरिए मुफ्त पानी मिल रहा है।

बंद पड़ी चीनी मिलों को पुनर्जीवित कर उन्हें इंटीग्रेटेड शुगर कॉम्प्लेक्स में बदला गया है, जहां चीनी के साथ एथेनॉल उत्पादन भी हो रहा है। इसके साथ ही प्रदेश में सक्रिय 96 लाख एमएसएमई इकाइयों के माध्यम से 3 करोड़ से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त हुए हैं।

उत्तर प्रदेश अब देश का बेहतरीन निवेश गंतव्य बन चुका है, जहां 34 सेक्टोरियल पॉलिसियों के दम पर लगभग 65 लाख युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार मिला है। सरकारी नौकरियों में शुचिता सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने पेपर लीक जैसे अपराधों के खिलाफ आजीवन कारावास और संपत्ति जब्ती का कड़ा कानून बनाया है।

पर्यटन के क्षेत्र में भी राज्य ने बड़ी छलांग लगाई है। पिछले वर्ष प्रयागराज महाकुंभ में 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई और साल भर में कुल 156 करोड़ से अधिक पर्यटकों का आगमन हुआ। पर्यटन क्षेत्र होटल, परिवहन और स्थानीय दुकानदारों की आर्थिकी को जबरदस्त मजबूती प्रदान कर रहा है।

सुरक्षा के मोर्चे पर अभूतपूर्व सुधार के कारण महिलाएं अब बेखौफ होकर नाइट शिफ्ट में काम कर रही हैं और बेटियां सुरक्षित स्कूल जा रही हैं। व्यापक आर्थिक सुधारों के चलते राज्य की प्रति व्यक्ति आय 43 हजार रुपये से तीन गुना बढ़कर 1.2 लाख रुपये से अधिक हो गई है।

इस वर्ष सरकार ने 9.12 लाख करोड़ रुपये का भारी-भरकम बजट पेश किया है। बिना कोई अतिरिक्त कर लगाए राज्य की जीएसडीपी 12校 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 36校 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। रिजर्व बैंक की रिपोर्ट भी पुष्टि करती है कि बैंकों का सबसे ज्यादा धन उत्तर प्रदेश के विकास में लग रहा है।

डबल इंजन सरकार ने लोक कल्याण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हुए 65 लाख गरीबों को आवास, 2.61 करोड़ परिवारों को शौचालय और 15 करोड़ जरूरतमंदों को हर महीने मुफ्त राशन की सुविधा उपलब्ध कराई है। इसके अतिरिक्त 10 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत योजना के तहत सालाना 5 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर प्रदान किया गया है।

प्राचीन भारतीय अर्थव्यवस्था का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि जब कृषि, मैन्युफैक्चरिंग और स्थानीय पर्यटन में सामूहिकता एवं समन्वय होता है, तो देश को आर्थिक महाशक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता। भारत ने सदियों के आक्रमणों और झंझावातों का सामना करते हुए भी अपने अस्तित्व को अक्षुण्ण बनाए रखा है।

सुदृढ़ बुनियादी ढांचे और लोक कल्याणकारी नीतियों से देश के विकास का मुख्य ग्रोथ इंजन बना नया उत्तर प्रदेश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 15 मई, 2026 को जनपद महराजगंज के मधुबन नगर नौतनवां में 208 करोड़ रुपये से अधिक लागत की 79 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण तथा शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व एवं मार्गदर्शन में डबल इंजन सरकार के विकासपरक कार्यों के परिणामस्वरूप राज्य में बड़े सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश वर्तमान में देश के सर्वश्रेष्ठ इंफ्रास्ट्रक्चर वाले राज्य के रूप में स्थापित हो चुका है।

उन्होंने कनेक्टिविटी और बुनियादी ढांचे के विकास पर प्रकाश डालते हुए बताया कि देश के कुल एक्सप्रेस-वे नेटवर्क में अकेले उत्तर प्रदेश की 60 प्रतिशत हिस्सेदारी मौजूद है। यह राज्य देश में सर्वाधिक हवाई अड्डों और मेट्रो रेल सेवाओं का सफल संचालन करने वाला प्रदेश बन चुका है। सबसे तेज गति से बढ़ती अर्थव्यवस्था बनने के साथ ही उत्तर प्रदेश ने देश और दुनिया के सामने सुरक्षा का एक बेहतरीन मॉडल पेश किया है, जिससे प्रदेश के नागरिकों का सम्मान हर जगह बढ़ा है।

समारोह के दौरान मुख्यमंत्री जी ने विभिन्न विभागों की जनकल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत चयनित लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र, प्रतीकात्मक चेक, टूल-किट, ट्रैक्टर और आवास की चाबियां सौंपी। इसके साथ ही बच्चों का अन्नप्राशन संपन्न हुआ और उन्होंने वहां आयोजित विकास प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया गया।

भारत और नेपाल के ऐतिहासिक संबंधों का उल्लेख करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि दोनों मित्र देश एक साझी विरासत और रोटी-बेटी के रिश्ते का प्रतिनिधित्व करते हैं। बौद्ध परिपथ का हिस्सा होने के कारण इस सीमावर्ती क्षेत्र पर वैश्विक नजर बनी रहती है, इसीलिए महराजगंज के विकास और सुरक्षा को प्रदेश सरकार ने अपनी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल रखा है। विकास की यह यात्रा बिना रुके और बिना डिगे अनवरत आगे बढ़ रही है।

महराजगंज के नौतनवां विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों की तीव्र गति की सराहना करते हुए उन्होंने बताया कि जनप्रतिनिधियों के जनहित से जुड़े प्रस्तावों को सरकार तत्काल मंजूरी प्रदान करती है। सही राजनीतिक चयन के कारण ही क्षेत्रों का कायाकल्प संभव हो सका है, जिससे युवाओं को रोजगार, किसानों को खुशहाली, बेटियों को सुरक्षा और गरीबों को सरकारी योजनाओं का पूरा लाभ मिल रहा है।

क्षेत्र की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में आए क्रांतिकारी सुधारों की चर्चा करते हुए उन्होंने बताया कि वर्ष 2017 से पूर्व इस इलाके में जापानी इंसेफेलाइटिस जैसी बीमारी महामारी का रूप ले चुकी थी, जिससे नौनिहालों को असमय जान गंवानी पड़ती थी। विगत नौ वर्षों में सरकार के योजनाबद्ध प्रयासों के कारण इंसेफेलाइटिस का पूरी तरह खात्मा हो चुका है और वर्तमान में महराजगंज का मेडिकल कॉलेज पूरी क्षमता के साथ क्रियाशील है।

पूर्ववर्ती व्यवस्थाओं में व्याप्त अराजकता को याद करते हुए उन्होंने कहा कि पहले सरकारी और गरीबों की संपत्तियों पर अवैध कब्जे होते थे, जिससे विकास अवरुद्ध था तथा किसान, युवा और महिलाएं परेशान थीं। वर्तमान कानून व्यवस्था के कारण अब कोई भी सुरक्षा में सेंध लगाने या गोवंश को नुकसान पहुँचाने का दुस्साहस नहीं कर सकता। युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार देने के साथ ही सरकारी नौकरियों से बड़े पैमाने पर जोड़ा जा रहा है।

सड़क मार्ग में हुए सुधारों को रेखांकित करते हुए उन्होंने बताया कि पहले गोरखपुर से महराजगंज और नौतनवां के बीच दो-लेन की सड़क भी उपलब्ध नहीं थी। वर्तमान में गोरखपुर-सोनौली मार्ग को चार-लेन का बनाया जा रहा है, जिससे दो घंटे की दूरी सिमटकर मात्र 45 से 50 मिनट की रह जाएगी। इसके साथ ही जंगल कौड़िया से सहजनवा के बीच बाईपास बन चुका है और कुशीनगर की ओर जाने वाले नए बाईपास का निर्माण भी युद्ध स्तर पर चल रहा है।

महराजगंज में तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आईटीआई और पॉलिटेक्निक जैसे कई संस्थान स्थापित किए जा चुके हैं तथा नए उद्योग लाने की प्रक्रिया गतिमान है। इसके अतिरिक्त, जनपद में बंद पड़े चीनी उद्योगों को पुनः सक्रिय करने के लिए एक विशेष कार्ययोजना तैयार की जा रही है। अन्नदाता किसानों के हित में रोहिन नदी पर बनैलिया बैराज का निर्माण संपन्न हुआ, जिससे हजारों एकड़ भूमि की सिंचाई सुगम होगी और किसानों की आमदनी बढ़ाने में मदद मिलेगी।

डबल इंजन सरकार ने वनटांगिया समुदाय के लोगों को आजादी के दशकों बाद उनके मूल अधिकारों से जोड़ते हुए पट्टे उपलब्ध कराए और उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज कराया। वर्तमान में इस वर्ग के प्रत्येक गरीब के पास अपना पक्का मकान, शौचालय, मुफ्त राशन और आयुष्मान कार्ड जैसी सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं। किसानों की उपज की पारदर्शी खरीद के लिए क्रय केंद्रों की पुख्ता व्यवस्था की गई है, जहाँ न्यूनतम समर्थन मूल्य सुनिश्चित किया जा रहा है।

सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और आस्था के सम्मान पर बात करते हुए उन्होंने बताया कि सदियों के संघर्ष के बाद अयोध्या धाम में भव्य श्रीराम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण संपन्न हुआ और हनुमान गढ़ी सहित काशी में श्री काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का विकास किया गया, जिसका आध्यात्मिक लाभ पूरे क्षेत्र को मिल रहा है।

वैश्विक परिस्थितियों और ईंधन संकट का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि पश्चिमी एशिया में जारी युद्ध के कारण तेल, डीजल, पेट्रोल और उर्वरक की वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित हुई है, जिससे भारत सरकार को भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ रहा है। इस वैश्विक मंदी और भारी दबाव के बावजूद सरकार ने देश में ईंधन के दामों को नियंत्रित रखने में बड़ी सफलता हासिल की है।

उत्तर प्रदेश के खेल इन्फ्रास्ट्रक्चर में हुआ इज़ाफ़ा, गोरखपुर में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण कार्यों का हुआ भूमिपूजन

उत्तर प्रदेश सरकार के खेल इन्फ्रास्ट्रक्चर को निरंतर विकसित करने के प्रयासों के तहत पूर्वी उत्तर प्रदेश के युवाओं को एक भव्य और आधुनिक खेल मंच मिल गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 16 मई, 2026 को जनपद गोरखपुर में 46 एकड़ भूमि पर 393 करोड़ रुपये की लागत से निर्मित होने वाले अत्याधुनिक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम के निर्माण के प्रथम चरण के कार्यों का भूमिपूजन कर शिलान्यास किया। इस अवसर पर केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप सिंह पुरी भी उपस्थित रहे।

यह अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम 30,000 दर्शक क्षमता का होने के साथ ही अत्याधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित किया जा रहा है। इसमें 04 हाई मास्ट स्पोर्ट्स लाइटिंग सिस्टम, मुख्य मैदान में 07 प्लेइंग पिच, 08 प्रैक्टिस पिच तथा प्रवेश एवं निकास के लिए 08 गेट की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। स्टेडियम को अग्नि सुरक्षा, भूकंपरोधी उपायों, ऊर्जा दक्ष प्रणालियों, एल0ई0डी0 प्रकाश व्यवस्था तथा अत्याधुनिक हीटिंग, वेंटिलेशन एवं एयर कंडीशनिंग से युक्त बनाया गया है। इसके अतिरिक्त 60 एकड़ भूमि को भविष्य के विस्तार के लिए आरक्षित रखा गया है।

कार्यक्रम के दौरान जानकारी दी गई कि इस स्टेडियम के निकट ही एक भव्य स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण भी कराया जाएगा, जहां इंडोर गेम, हॉकी तथा अन्य खेलकूद गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाएगा। इस परियोजना के फलस्वरूप क्षेत्र में होटल, रेस्टोरेंट और बाजारों का विकास सुनिश्चित होगा। पूर्व में उपेक्षित और बंजर रही इस शासकीय भूमि को पूरी तरह से अतिक्रमण मुक्त कराकर लोक कल्याण तथा विकास की इस बड़ी परियोजनाके लिए समर्पित किया गया है। कानून व्यवस्था के सुदृढ़ होने से प्रदेश में भयमुक्त वातावरण का सृजन हुआ है, जिसने विकास और रोजगार के नए अवसरों को गति प्रदान की है।

खिलाड़ियों के प्रोत्साहन के लिए उत्तर प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है, जिसने विशेष खेल नीति तैयार की है। इसके अंतर्गत ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियाड व वर्ल्ड चैंपियनशिप में पदक प्राप्त करने वाले 534 से अधिक प्रतिभाशाली युवाओं को सीधी भर्ती के माध्यम से शासकीय नौकरियां प्रदान की गई हैं। कई विशिष्ट खिलाड़ियों को डिप्टी एस0पी0, नायब तहसीलदार, यात्री/माल कर अधिकारी, जिला युवा कल्याण अधिकारी, जिला पंचायतीराज अधिकारी, खंड विकास अधिकारी तथा क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी के पदों पर नियुक्तियां दी जा चुकी हैं। आगामी समय में भी नेशनल और इंटरनेशनल चैंपियनशिप के पदक विजेताओं के लिए 500 पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है।

राष्ट्रीय स्तर पर खेल संस्कृति को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में 'खेलो इंडिया', 'फिट इंडिया मूवमेंट' तथा 'सांसद खेलकूद प्रतियोगिता' जैसी पहलों ने देश में एक सकारात्मक माहौल तैयार किया है। इसी क्रम में भारत वर्ष 2030 के कॉमनवेल्थ गेम्स और वर्ष 2036 के ओलंपिक की मेजबानी के लिए अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर रहा है ताकि देश की खेल प्रतिभाओं को अपनी ही धरती पर सामर्थ्य दिखाने का अवसर मिल सके। राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक गांव में खेल का मैदान, विकासखंड स्तर पर मिनी स्टेडियम, जिला स्तर पर स्टेडियम तथा प्रत्येक कमिश्नरी स्तर पर एक स्पोर्ट्स कॉलेज विकसित करने की दिशा में कार्य किया जा रहा है। मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निर्माण लगभग पूर्ण हो चुका है और वाराणसी में भी एक इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का निर्माण प्रगति पर है।

गोरखपुर में क्रिकेट स्टेडियम के अलावा वेटरनरी कॉलेज का निर्माण कार्य भी तेजी से चल रहा है, जो पशुधन के उपचार का एक बड़ा माध्यम बनेगा। बुनियादी ढांचे के विकास की दृष्टि से पिछले एक दशक में व्यापक परिवर्तन आया है और गोरखपुर से वाराणसी तथा लखनऊ जैसे प्रमुख शहरों की दूरी और यात्रा का समय घटकर अत्यंत कम रह गया है। संपूर्ण प्रदेश को फोर लेन कनेक्टिविटी, एक्सप्रेस-वे के विस्तृत नेटवर्क और बेहतरीन हवाई अड्डों की सुविधा से जोड़कर विकास की नई जीवन रेखाएं तैयार की गई हैं। वैश्विक अनिश्चितताओं और पश्चिम एशिया संकट के कठिन समय में भी देश का ऊर्जा प्रबंधन अत्यंत उत्कृष्ट रहा है और उत्तर प्रदेश बायोगैस तथा कंप्रेस्ड गैस जैसे हरित ऊर्जा क्षेत्रों में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है।

केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री श्री कमलेश पासवान ने इस अवसर पर कहा कि इस अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की सौगात से क्षेत्र के क्रिकेट प्रेमियों को स्थानीय स्तर पर ही मैच और आईपीएल देखने का अवसर प्राप्त होगा। इस वृहद खेल अवसंरचना के पूर्ण होने से न केवल पूर्वी उत्तर प्रदेश का खेल परिदृश्य बदलेगा, बल्कि नए उद्योगों की स्थापना के साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन को भी भारी संबल प्राप्त होगा।

अनुदेशकों को मिली मानदेय में भारी वृद्धि और कैशलेस स्वास्थ्य सुरक्षा

प्रदेश की बुनियादी शिक्षा व्यवस्था को सशक्त बनाने तथा शिक्षण व्यवस्था से जुड़े हर वर्ग को गरिमापूर्ण जीवन प्रदान करने के प्रयासों को एक नया विस्तार मिल गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 17 मई, 2026 को लोक भवन, लखनऊ में बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा शैक्षणिक सत्र 2026-27 में समग्र शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 24,717 अंशकालिक अनुदेशकों की मानदेय वृद्धि के उपलक्ष्य में आयोजित 'अनुदेशक सम्मान समारोह' के अवसर पर अनुदेशकों को मानदेय का प्रतीकात्मक चेक वितरित किया। इस निर्णय के तहत 01 अप्रैल, 2026 से अनुदेशकों का मासिक मानदेय 09 हजार रुपये से बढ़ाकर 17 हजार रुपये कर दिया गया है। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक, कैबिनेट मंत्री श्री मनोज कुमार पाण्डेय तथा बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री सन्दीप सिंह भी उपस्थित रहे।

समारोह के दौरान शासकीय प्रतिबद्धता को दोहराते हुए स्पष्ट किया गया कि सशक्त और समर्थ राष्ट्र के निर्माण के लिए शिक्षा की नींव को मजबूत करना सबसे कठिन और महत्वपूर्ण कार्य होता है। अनुदेशकों व शिक्षामित्रों के इस गरिमापूर्ण कार्य को सम्मानजनक बनाने के लिए मानदेय वृद्धि के साथ ही उन्हें 05 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवर भी उपलब्ध कराया गया है। इसके अंतर्गत लगभग 01 लाख 43 हजार शिक्षामित्रों, 24,296 अनुदेशकों, समस्त शिक्षकों तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों और उनके परिवारों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा के दायरे में लाया गया है। इस सुविधा के सुचारू संचालन के लिए सभी अनुदेशकों को बेसिक शिक्षा विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण कराने के निर्देश दिए गए हैं ताकि आगामी सप्ताह से ही कार्डों का वितरण सुनिश्चित किया जा सके।

शैक्षणिक गुणवत्ता और छात्र-शिक्षक अनुपात को आदर्श स्तर पर बनाए रखने के लिए नगरीय क्षेत्र के परिषदीय विद्यालयों में 10 हजार नए शिक्षकों की भर्ती हेतु अधियाचन भेजा जा चुका है और यह प्रक्रिया शीघ्र ही प्रारंभ होने वाली है। इसके साथ ही उच्च प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा के स्तर को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से 20 हजार नए अनुदेशकों की नियुक्ति की प्रक्रिया को भी इस अभियान से जोड़ा जा रहा है। वर्तमान में प्रदेश के उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 8,469 कला शिक्षा, 9,645 स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा तथा 6,192 कार्यानुभव शिक्षा अनुदेशक पूरी निष्ठा के साथ कार्यरत हैं।

वर्ष 2011-12 में अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंतर्गत शुरू हुई इस व्यवस्था के बाद से लंबे समय तक अनुदेशकों के मानदेय में कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया था। वर्ष 2022 में प्रदेश सरकार द्वारा मानदेय में 2,000 रुपये की प्रारंभिक वृद्धि की गई थी, जिसके बाद वर्तमान में संवेदनशीलता का परिचय देते हुए इस मानदेय को सीधे 17,000 रुपये निर्धारित कर दिया गया। महिला अनुदेशकों की सहूलियत के लिए पूर्व में ही 06 माह के मानदेय के साथ मातृत्व अवकाश की सुविधा तथा स्वेच्छा से विद्यालय परिवर्तन का विकल्प प्रदान किया गया, जिसका लाभ 04 हजार से अधिक महिला अनुदेशकों ने उठाया।

वर्ष 2017 से पूर्व की अव्यवस्थाओं को दूर करते हुए वर्तमान शासकीय नीतियों के तहत 'स्कूल चलो अभियान' तथा 'ऑपरेशन कायाकल्प' की रूपरेखा तैयार की गई। इस वृहद अभियान के फलस्वरूप 96 प्रतिशत विद्यालयों में छात्र, शिक्षक तथा बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की गई, जिसकी सफलता को नीति आयोग ने देश के समक्ष एक 'सक्सेस स्टोरी' के रूप में प्रस्तुत किया। इन सामूहिक प्रयासों के कारण विद्यालयों में ड्रॉप आउट रेट 17-18 प्रतिशत से घटकर मात्र 03 प्रतिशत पर आ गया, जिसे शून्य तक ले जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है ताकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के आत्मनिर्भर और विकसित भारत का सपना साकार हो सके।

प्रत्येक बच्चे के भीतर छुपी विशिष्ट खेल, कला या विषयगत प्रतिभा को उजागर करने की जिम्मेदारी अनुदेशकों को सौंपी गई है, जिसकी शुरुआत आत्म अनुशासन और समयबद्धता से होती है। बच्चों को संस्कारवान, योग्य और हर चुनौती का सामना करने में सक्षम बनाने के लिए विद्यालयों में स्वच्छता और श्रमदान को बढ़ावा दिया जा रहा है। वर्तमान में बुनियादी शिक्षा व्यवस्था के तहत लगभग एक करोड़ 60 लाख बच्चे नामांकित हैं, जिनके अभिभावकों के खातों में यूनिफॉर्म, स्वेटर और जूते-मोजे के लिए सीधे धनराशि भेजी जा रही है।

वंचित और श्रमिक वर्ग के बच्चों के लिए विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचे से युक्त 18 अटल आवासीय विद्यालयों का संचालन किया जा रहा है, जहां बच्चों के आवास और भोजन का संपूर्ण व्यय सरकार वहन कर रही है। इसके साथ ही प्रत्येक जनपद में प्री-प्राइमरी से 12वीं कक्षा तक की आधुनिक शिक्षा, खेल और कौशल विकास की सुविधाओं से युक्त दो-दो 'मुख्यमंत्री मॉडल कंपोजिट विद्यालय' स्वीकृत किए गए हैं। बेटियों की उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए पूर्व में संचालित 746 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों को 12वीं कक्षा तक उच्चीकृत किया गया है तथा शेष विकास खंडों में भी नए विद्यालयों की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता जारी की गई है।

प्रशासनिक पारदर्शिता के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया गया है, जो पूर्णतः निष्पक्ष प्रक्रिया के तहत शिक्षकों का चयन कर रहा है। वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों और पश्चिम एशिया संकट के कारण उत्पन्न आर्थिक चुनौतियों के बीच भारत का कुशल नेतृत्व देश को निरंतर प्रगति की राह पर अग्रसर रखे हुए है। परिषदीय विद्यालयों में स्मार्ट क्लास, डिजिटल लाइब्रेरी और आईसीटी लैब्स जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं के समावेश से उत्तर प्रदेश अब नवाचार का एक प्रमुख केंद्र बनकर उभर रहा है।

पारदर्शी चयन प्रणाली से उत्तर प्रदेश को मिले नौ सौ बत्तीस नए प्रशासनिक कर्णधार

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 18 मई, 2026 को लोक भवन सभागार में उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित उत्तर प्रदेश सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा-2024 के अंतर्गत 21 विभागों में विभिन्न पदों पर चयनित 932 अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह को संबोधित किया। इस भव्य अवसर पर उन्होंने सफल अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान करते हुए कहा कि गति को प्रगति की ओर वही ले जा सकता है, जिसका चयन ईमानदारी से हुआ हो और जिसने अपने परिश्रम से अपना स्थान प्राप्त किया है। उन्होंने इस बात पर विशेष बल दिया कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने भर्ती की पूरी प्रक्रिया को पूर्ण पारदर्शिता व शुचितापूर्ण तरीके से संपन्न कराया है, जिसके परिणामस्वरूप यह मेधावी प्रतिभाएं उत्तर प्रदेश सरकार का अभिन्न हिस्सा बनीं।

परिश्रम को सफलता की ऊंचाई तक पहुंचाने का एकमात्र माध्यम बताते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जब व्यक्तिगत पुरुषार्थ एक ईमानदार और निष्पक्ष व्यवस्था से जुड़ता है, तो ऐसे ही सकारात्मक परिणाम सामने आते हैं। उन्होंने नवचयनित अधिकारियों व उनके अभिभावकों को बधाई देते हुए विश्वास व्यक्त किया कि सभी अधिकारी उत्तर प्रदेश के चहुंमुखी विकास तथा प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के विकसित भारत की संकल्पना को साकार करने में पूरी तत्परता से अपना योगदान देंगे। उत्तर प्रदेश जैसे विशाल और विविधताओं से भरे राज्य में कार्य करने को उन्होंने एक गौरव की बात बताया।

भर्ती प्रक्रिया के पारदर्शी और शुचितापूर्ण होने की अनिवार्यता को रेखांकित करते हुए मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यदि चयन की प्रक्रिया निष्पक्ष न हो, तो चयनित लोगों से ईमानदारीपूर्वक परिणाम देने तथा प्रदेश को प्रगति व समृद्धि की नई ऊंचाइयों पर ले जाने की अपेक्षा करना व्यर्थ है। उन्होंने वर्ष 2017 से पूर्व की व्यवस्था पर प्रहार करते हुए कहा कि पूर्ववर्ती समय में सिफारिश और पैसे के बल पर होने वाला चयन राज्य को प्रगति की बजाय दुर्गति की ओर ले जाता था। वर्तमान सरकार की नीतियों के कारण ही आज की युवा पीढ़ी को स्कूली शिक्षा से लेकर प्रतियोगी परीक्षाओं तक नकलविहीन और पारदर्शी व्यवस्था देखने को मिली है।

उत्तर प्रदेश को ईश्वर की असीम कृपा का राज्य बताते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि यह प्रदेश प्राकृतिक संसाधनों, उर्वरा भूमि, प्रचुर जल संसाधन और देश के सबसे मजबूत एमएसएमई बेस से समृद्ध है। एक समय पहचान के संकट से जूझकर बीमारू बन चुके इस राज्य को विगत 9 वर्षों के अथक प्रयासों से देश की अर्थव्यवस्था के 'ग्रोथ इंजन' के रूप में स्थापित किया गया। टीम भावना के साथ कार्य करते हुए सरकार ने राज्य की अर्थव्यवस्था और प्रति व्यक्ति आय को तीन गुना करने में सफलता प्राप्त की है, जिससे उत्तर प्रदेश बॉटम-थ्री से निकलकर देश के टॉप-थ्री राज्यों में शुमार हुआ है।

मुख्यमंत्री जी ने नवचयनित अधिकारियों को मार्गदर्शन देते हुए कहा कि भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था में उत्तर प्रदेश के भीतर कार्य करने का अनुभव सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि यहाँ सम और विषम दोनों परिस्थितियों में परिणाम देने होते हैं। उन्होंने अधिकारियों को सचेत किया कि सेवाकाल के शुरुआती 10 वर्षों की कड़ी मेहनत उनके पूरे 30-35 वर्षों के प्रशासनिक जीवन और भविष्य के लिए एक मजबूत नींव का कार्य करेगी। उन्होंने सभी से शासकीय कार्यों को टालने की बजाय उसी दिन निपटाने की कार्यसंस्कृति विकसित करने का आह्वान किया।

मध्य क्षेत्रीय परिषद की बैठक में प्रस्तुत हुआ उत्तर प्रदेश के अभूतपूर्व विकास का मॉडल

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 19 मई, 2026 को बस्तर, छत्तीसगढ़ में आयोजित मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक में उत्तर प्रदेश की अभूतपूर्व विकास यात्रा और विभिन्न क्षेत्रों की ऐतिहासिक उपलब्धियों का विवरण प्रस्तुत किया। उन्होंने बैठक में विचार व्यक्त करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नए भारत की संकल्पना का साकार रूप हर क्षेत्र में दिख रहा है और अतीत में चुनौतीपूर्ण रहा यह अंचल अब राष्ट्रीय नीति-निर्धारण की मुख्यधारा में शामिल हो चुका है। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के कुशल नेतृत्व की सराहना करते हुए स्पष्ट किया कि जो उत्तर प्रदेश कभी बीमारू राज्य था, वह विगत 9 वर्षों में देश के विकास की धुरी बनकर उभरा है, जहाँ कानून-व्यवस्था, जन-कल्याणकारी योजनाओं, बुनियादी ढांचे और रोजगार में व्यापक सकारात्मक परिवर्तन आया।

प्रदेश सरकार द्वारा समाज के हर वर्ग के उत्थान के लिए उठाए गए कदमों की चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री जी ने जल जीवन मिशन को नारी गरिमा और ईज़ ऑफ लिविंग से जोड़ा। मिशन के प्रारम्भ में प्रदेश के मात्र 1.96 प्रतिशत परिवारों को पाइप पेयजल सुलभ था, जो वर्ष 2026 में बढ़कर 91.25 प्रतिशत से अधिक हो चुका है और इसके तहत 33,157 सौर ऊर्जा आधारित योजनाएं भी संचालित हैं। डिजिटल क्रांति के साथ बढ़ते साइबर अपराधों से निपटने के लिए प्रदेश सरकार की कटिबद्धता को रेखांकित करते हुए उन्होंने बताया कि वर्ष 2016 के मात्र 2 साइबर थानों के मुकाबले वर्तमान में सभी 75 जनपदों में साइबर थाने और हेल्प डेस्क पूरी तरह सक्रिय हैं।

ई-गवर्नेन्स के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को अग्रणी बताते हुए मुख्यमंत्री जी ने अवगत कराया कि राज्य की सभी 57,695 ग्राम पंचायतों में 2.33 लाख से अधिक कॉमन सर्विस सेण्टर संचालित हैं, जिनसे 44 करोड़ से अधिक नागरिक लाभान्वित हुए हैं। तकनीक को बढ़ावा देने के उद्देश्य से प्रदेश सरकार द्वारा यू0पी0 ए0आई0 मिशन हेतु 225 करोड़ रुपये तथा न्यू इमर्जिंग टेक्नोलॉजी के लिए 100 करोड़ रुपये का बजट प्राविधानित किया गया। स्वास्थ्य और पोषण के मोर्चे पर मुख्यमंत्री जी ने प्रतिमाह करोड़ों बच्चों और गर्भवती महिलाओं को अनुपूरक पुष्टाहार देने तथा 'सम्भव 5.0' अभियान के माध्यम से स्टंटिंग और वेस्टिंग की दरों में भारी गिरावट लाने की जानकारी दी। इसके साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत 5.73 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड सृजित किए जा चुके हैं।

सुरक्षा के वातावरण और रूल ऑफ लॉ को धरातल पर उतारने की प्रतिबद्धता दोहराते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पॉक्सो एक्ट में दर्ज मामलों के त्वरित निस्तारण में उत्तर प्रदेश देश में द्वितीय स्थान पर है। आधुनिक तकनीक के समन्वय से आपातकालीन सेवा यू0पी0-112 का रिस्पॉन्स टाइम वर्ष 2023 के 9:50 मिनट से घटाकर जनवरी-अप्रैल, 2026 में 6:24 मिनट कर दिया गया। नगरीय विकास के क्षेत्र में अमृत और स्मार्ट सिटी मिशन के तहत मास्टर प्लान तैयार करने की प्रक्रिया तेज की गई है।

प्रधानमंत्री आवास योजना के क्रियान्वयन में उत्तर प्रदेश को अग्रणी राज्य बताते हुए मुख्यमंत्री जी ने कहा कि शहरी क्षेत्र में स्वीकृत आवासों के सापेक्ष 96.5 प्रतिशत निर्माण कार्य पूर्ण किया गया। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में सुचारू विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ ही वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए राज्य में 4.49 लाख से अधिक बैंकिंग केंद्रों का नेटवर्क तैयार किया गया है, जिससे सभी 98,047 ग्राम आच्छादित हैं। शिक्षा के क्षेत्र में बुनियादी सुधारों का उल्लेख करते हुए उन्होंने बताया कि 'स्कूल चलो अभियान' के माध्यम से प्राथमिक स्तर पर ड्रॉप आउट दर शून्य हो गई है, जिसमें ऑपरेशन कायाकल्प की बड़ी भूमिका रही।

सहकार से समृद्धि' के मंत्र के साथ पैक्स समितियों को बहुउद्देशीय बनाते हुए उन्हें जन औषधि केंद्र और किसान समृद्धि केंद्र के रूप में विकसित किया गया है, जिसमें उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर रहा। नवीन सहकारी समितियों के गठन के साथ-साथ विश्व की सबसे बड़ी अनाज भण्डारण योजना पर भी तेजी से कार्य चल रहा है। श्रमिकों के हितों की रक्षा को सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए मुख्यमंत्री जी ने लेबर ई-कोर्ट 'श्रम न्याय सेतु' पोर्टल लॉन्च करने की जानकारी दी, जो श्रम विवादों के पारदर्शी समाधान की व्यवस्था करता है। मुख्यमंत्री जी ने पूर्ण विश्वास प्रकट किया कि मध्य क्षेत्रीय परिषद सहकारी संघवाद को सुदृढ़ करते हुए 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' के संकल्प को गति प्रदान करती रहेगी।

यू0पी0 डाटा सेण्टर क्लस्टर परियोजना उत्तर प्रदेश के ए0आई0 मिशन की बुनियादी संरचना तैयार करेगी

उत्तर प्रदेश को डिजिटल और औद्योगिक महाशक्ति बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने एक बड़ा रणनीतिक कदम उठाया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ज ने 20 मई, 2026 को लखनऊ में अपने सरकारी आवास पर आयोजित एक उच्चस्तरीय बैठक में प्रदेश के आर्थिक भविष्य से जुड़े तीन अत्यंत महत्वपूर्ण विषयों की गहन समीक्षा की। इस बैठक में उत्तर प्रदेश डाटा सेण्टर क्लस्टर (यू0पी0डी0सी0सी0), प्रोजेक्ट गंगा तथा गेहूँ के इन-हाउस प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए मण्डी शुल्क एवं मण्डी सेस में सम्भावित छूट की रूपरेखा तय की गई।

समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने स्पष्ट किया कि यू0पी0 डाटा सेण्टर क्लस्टर परियोजना उत्तर प्रदेश के ए0आई0 मिशन की बुनियादी संरचना तैयार करेगी। उन्होंने निर्देश दिया कि डाटा सेण्टर क्लस्टर केवल एन0सी0आर0 क्षेत्र तक सीमित न रहकर प्रदेश के अन्य हिस्सों से भी जोड़ा जाए। इसकी शुरुआत बुन्देलखण्ड औद्योगिक विकास प्राधिकरण (बीडा) क्षेत्र से करने की बात कही गई, जहाँ बड़े पैमाने पर भूमि उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने टाटा समूह सहित बड़ी टेक कम्पनियों से संवाद स्थापित कर लखनऊ को 'ए0आई0 सिटी' के रूप में विकसित करने की दिशा में तेजी से कार्य करने का निर्देश दिया।

बैठक में प्रस्तुतीकरण के माध्यम से स्पष्ट किया गया कि उत्तर प्रदेश डाटा सेण्टर क्लस्टर, प्रदेश को भारत और ग्लोबल साउथ का सबसे बड़ा ए0आई0 कम्प्यूट पावर सेण्टर बनाने की एक दीर्घकालिक रणनीति है। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश को आर्टिफिशियल इण्टेलिजेंस, डेटा सेण्टर, क्लाउड इन्फ्रास्ट्रक्चर और हाई-टेक डिजिटल मैन्युफैक्चरिंग का वैश्विक केन्द्र बनाना है। यह परियोजना अगले 50 वर्षों के लिए उत्तर प्रदेश की नई आर्थिक संरचना का खाका तैयार करती है, जिसके तहत वर्ष 2040 तक 05 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था, 1.5 लाख से अधिक प्रत्यक्ष रोजगार और 05 गीगावॉट ए0आई0 कम्प्यूट कॉरिडोर विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है।

भविष्य की आर्थिक आवश्यकताओं को देखते हुए बैठक में यह रेखांकित किया गया कि वर्ष 2040 तक दुनिया की नई अर्थव्यवस्था ए0आई0, क्लाउड, साइबर सिक्योरिटी, सेमीकण्डक्टर, इलेक्ट्रिक व्हीकल, रोबोटिक्स और स्पेस टेक्नोलॉजी जैसे 'फ्यूचर एरेना' के इर्द-गिर्द विकसित होगी, जिनका संयुक्त वैश्विक बाजार 29 से 48 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँचने का अनुमान है। भारत के लिए ए0आई0 सॉफ्टवेयर एण्ड सर्विसेज, क्लाउड सर्विसेज, साइबर सिक्योरिटी, सेमीकण्डक्टर्स, एयरोस्पेस और ई0वी0 जैसे सेक्टर भविष्य के प्रमुख आर्थिक इंजन की भूमिका निभाएंगे।

तकनीकी विशिष्टताओं के मामले में उत्तर प्रदेश को 'एशिया का मोस्ट सिक्योर, स्केलेबल एवं कनेक्टेड इनलैण्ड ए0आई0 टेरिटरी' के रूप में प्रस्तुत किया गया। देश के लगभग सभी प्रमुख फाइबर नेटवर्क उत्तर प्रदेश से होकर गुजरते हैं और राज्य भारत के सभी समुद्री केबल लैण्डिंग प्वाइण्ट्स से सीधे जुड़ा हुआ है। राज्य के भीतर 05 मिलीसेकण्ड से कम लेटेन्सी तथा मुम्बई और चेन्नई जैसे डिजिटल हब तक 5-12 मिलीसेकण्ड कनेक्टिविटी की सुविधा उपलब्ध है, जिससे वैश्विक टेक कम्पनियों के लिए उत्तर प्रदेश कम लागत, बेहतर स्केलेबिलिटी और अधिक नेटवर्क रिडण्डेंसी वाला आदर्श ए0आई0 इन्फ्रास्ट्रक्चर हब बनकर उभरा है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 'प्रोजेक्ट गंगा' यानी गवर्नेण्ट असिस्टेड नेटवर्क फॉर ग्रोथ एंड एडवांसमेण्ट की समीक्षा करते हुए डिजिटल उद्यमियों के रूप में चुने जाने वाले युवाओं को गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण देने की आवश्यकता जताई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के तेजी से विस्तार और कार्यों में पूर्ण पारदर्शिता सुनिश्चित करते हुए शुरुआत से ही डिजिटल उद्यमियों को उचित इन्सेंटिव उपलब्ध कराने की हिदायत दी।

इस महत्वाकांक्षी पहल के तहत ग्रामीण उत्तर प्रदेश में हाई-स्पीड ब्रॉडबैण्ड नेटवर्क पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है, जिसके माध्यम से 10 हजार से अधिक युवाओं को डिजिटल सर्विस प्रोवाइडर (डी0एस0पी0) के रूप में विकसित करने की योजना बनाई गई, जिससे लगभग 50 हजार प्रत्यक्ष और 01 लाख से अधिक अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने का मार्ग प्रशस्त हुआ। इस अभियान में महिला उद्यमिता को विशेष प्राथमिकता देते हुए लगभग 50 प्रतिशत महिला उद्यमियों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया। वास्तविक डिजिटल परिवर्तन के लिए केवल मोबाइल इण्टरनेट के स्थान पर हाई-स्पीड ब्रॉडबैण्ड को आवश्यक माना गया, जो ए0आई0 आधारित कृषि, ड्रोन मॉनिटरिंग, स्मार्ट विलेज, वर्चुअल लैब, टेलीमेडिसिन और क्लाउड कम्प्यूटिंग जैसी सेवाओं के लिए मजबूत आधार बनेगा।

उत्तर प्रदेश सरकार की इस योजना के तहत प्रत्येक डी0एस0पी0 को 05 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। यह परियोजना प्रारम्भिक चरण में 21 प्राथमिक जिलों में 'प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट' के रूप में शुरू होने जा रही है, जिसके सफल क्रियान्वयन के बाद इसे पूरे प्रदेश में विस्तार दिया जाएगा।

कृषि और व्यापारिक सुधारों की दिशा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने गेहूँ के इन-हाउस प्रसंस्करण को बढ़ावा देने की रणनीति की समीक्षा करते हुए मण्डी टैक्स और मण्डी शुल्क व्यवस्था में सुधार की आवश्यकता पर विशेष बल दिया। उन्होंने प्रदेश की मण्डियों को आधुनिक, स्वच्छ और आकर्षक बनाने का निर्देश जारी किया। मण्डियों में साफ-सफाई, रंगाई-पुताई, पर्वों के दौरान भव्य लाइटिंग, अतिक्रमण हटाने और बेहतर प्रबन्धन की चाक-चौबंद व्यवस्था सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए गए।

जलवायु परिवर्तन के दृष्टिगत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने अल नीनो के सम्भावित प्रभाव का विशेष उल्लेख किया। उन्होंने आगाह किया कि आगामी वर्षों में फसलों पर इसका विपरीत असर पड़ सकता है, इसलिए प्रदेश को खाद्यान्न सुरक्षा के लिए अभी से मुस्तैद रहना होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने स्पष्ट आदेश दिया कि राज्य के खाद्यान्न भण्डार हर हाल में पर्याप्त और मजबूत बने रहने चाहिए ताकि किसी भी विपरीत परिस्थिति का सामना किया जा सके।

आर्थिक आंकड़ों के विश्लेषण से स्पष्ट हुआ कि उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा गेहूँ उत्पादक राज्य है, जहाँ वर्ष 2025-26 में लगभग 372 लाख मीट्रिक टन गेहूँ उत्पादन का अनुमान रहा, जिसके बावजूद सीमित प्रसंस्करण क्षमता होने के कारण बड़ी मात्रा में गेहूँ कच्चे अनाज के रूप में दूसरे राज्यों में चला जाता है, जिससे मूल्य संवर्धन, जी0एस0टी0 राजस्व और रोजगार के बड़े अवसर प्रदेश से बाहर चले जाते हैं। उच्चस्तरीय समीक्षा रिपोर्ट में यह निष्कर्ष निकाला गया कि यदि राज्य के भीतर ही गेहूँ प्रसंस्करण को प्रभावी ढंग से बढ़ावा मिले तो रोजगार, बिजली खपत, जी0एस0टी0 संग्रह और खाद्य उद्योगों में अभूतपूर्व विस्तार संभव है। इसी परिप्रेक्ष्य में समिति ने महत्वपूर्ण सुझाव दिया कि उत्तर प्रदेश में पंजीकृत मिलों द्वारा राज्य के भीतर प्रसंस्करण हेतु खरीदे गए गेहूँ पर मण्डी शुल्क एवं विकास उपकर में विशेष छूट प्रदान की जाए, हालांकि व्यापारिक गतिविधियों पर यह छूट लागू नहीं की जाएगी।

शिष्टाचार भेंट

अपने सरकारी आवास पर 18 मई 2026 को भारत के पूर्व राष्ट्रपति माननीय श्री रामनाथ कोविंद जी से शिष्टाचार भेंट करते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने नई दिल्ली में 17 मई,2026 को गृहमंत्री श्री अमित शाह जी से शिष्टाचार भेंट की।

मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ जी ने 16 मई, 2026 को गोरखपुर में डिजिटल जनगणना के प्रथम चरण 'स्वगणना' के अंतर्गत ऑनलाइन प्रपत्र भरकर प्रदेशवासियों से 21 मई तक इस प्रक्रिया में सक्रिय सहभागिता की अपील की।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की अध्यक्षता में 18 मई, 2026 को मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय

» मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश पं0 दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गो अनुसंधान संस्थान, मथुरा तथा कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान विभाग के अन्तर्गत संचालित आचार्य नरेन्द्रदेव कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, कुमारगंज, अयोध्या एवं सरदार वल्लभ भाई पटेल, कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय, मेरठ में अध्ययनरत पशु चिकित्सा के छात्रों का इण्टर्नशिप भत्ता 4,000 रुपये प्रतिमाह से बढ़ाकर 12,000 रुपये प्रतिमाह किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। इस सम्बन्ध में सम्भावित अतिरिक्त व्यय-भार की पूर्ति विश्वविद्यालय को प्रदत्त शासकीय अनुदान के अन्तर्गत गैर वेतन मद से सम्बन्धित लेखा शीर्ष से की जाएगी।

» मंत्रिपरिषद ने मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेशों के अनुपालन में उत्तर प्रदेश राज्य के त्रिस्तरीय पंचायत निकायों में आरक्षण प्रदान करने के आशय से पिछड़ेपन की प्रकृति और प्रभावों की समकालीन, सतत्, अनुभवजन्य जांच व अध्ययन करने और इस प्रकार निर्धारित अन्य पिछड़े वर्ग के व्यक्तियों को निकायवार आनुपातिक आरक्षण दिए जाने हेतु उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।

» मंत्रिपरिषद ने डॉ0 राम मनोहर लोहिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज़, गोमतीनगर विस्तार, सेक्टर-7, लखनऊ स्थित संस्थान के नवीन परिसर (शहीद पथ) में 1,010 बेडेड मल्टी स्पेशियलिटी इमरजेन्सी सेण्टर अस्पताल, Teaching ब्लॉक व नवीन ओ0पी0डी0 ब्लॉक के निर्माण कार्य सम्बन्धी प्रायोजना की आकलित लागत 855 करोड़ 04 लाख 34 हजार रुपये मात्र के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।

» मंत्रिपरिषद ने राजकीय मेडिकल कॉलेज, प्रयागराज से सम्बद्ध स्वरूप रानी नेहरू चिकित्सालय परिसर के विस्तार/उच्चीकरण हेतु चिकित्सालय एवं महात्मा गांधी मार्ग से जुड़ी पूल्ड हाउसिंग की मौजा नीबी बाग, परगना व तहसील सदर स्थित नॉन जेड0ए0 खतौनी फसली सन् 1428 के खाता संख्या-38, 39 तथा 44 में से 31,314 वर्गमीटर भूमि चिकित्सा शिक्षा विभाग के पक्ष में 01 रुपये वार्षिक किराए पर 90 वर्ष के पट्टे पर हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।

» मंत्रिपरिषद ने लखनऊ मेट्रो फेज़-1 बी ईस्ट-वेस्ट कॉरिडोर (चारबाग से वसंतकुंज) परियोजना की भारत सरकार द्वारा अनुमोदित लागत 5801.05 करोड़ रुपये तथा न्याय विभाग द्वारा संशोधित/विधीक्षित एम0ओ0यू0 के आलेख के अनुसार आवासन एवं शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार एवं उत्तर प्रदेश मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मध्य निष्पादित होने वाले एम0ओ0यू0 एवं इसमें अंकित राज्य सरकार की भूमिका एवं दायित्वों के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।

» मंत्रिपरिषद ने आगरा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के अन्तर्गत मेट्रो कॉरिडोर-II (आगरा कैण्ट से कालिन्दी विहार) में मेट्रो स्टेशन एवं वायडक्ट सेक्शन के निर्माण हेतु मौजा चक अव्वल, तहसील सदर, आगरा के खसरा संख्या-618 नजूल भूखण्ड संख्या-1619 में संचालित क्षेत्रीय सेवायोजन कार्यालय परिसर की पार्क के रूप में रिक्त नजूल भूमि में से 550 वर्गमीटर भूमि उ0प्र0 मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लि0 को प्रभावी जिलाधिकारी सर्किल दर पर छूट प्रदान करते हुए कतिपय शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन निःशुल्क आवंटित/हस्तांतरित करने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।

» मंत्रिपरिषद ने 765/400 के0वी0 मीरजापुर पूलिंग उपकेन्द्र एवं सम्बन्धित पारेषण लाइनों के निर्माण सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है। प्रदेश में बढ़ती विद्युत मांग की पूर्ति हेतु प्रस्तावित तापीय एवं पम्प स्टोरेज परियोजनाओं द्वारा उत्पादित ऊर्जा की समुचित निकासी के लिए इस परियोजना का निर्माण किया जाएगा।

» मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश निजी विश्वविद्यालय अधिनियम-2019 के अन्तर्गत निजी क्षेत्र में सरदार पटेल एपेक्स यूनिवर्सिटी, मीरजापुर की स्थापना हेतु उसकी प्रायोजक संस्था एपेक्स वेलकेयर ट्रस्ट, वाराणसी को कतिपय शर्तों तथा अधिनियम की धारा-6 के प्राविधानों के अन्तर्गत आशय पत्र निर्गत किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।